साक्षी सुरक्षा योजना

इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकनोमिक टाइम्स, (05 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के द्वारा साक्षी सुरक्षा योजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को कहा है कि जब तक यह योजना संसद में कानून का रूप न अपना ले, तब तक लागू करें। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की योजना में कुछ परिवर्तन भी किये हैं।
- यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होगी।

आवश्यकता क्यों?

- यह देखा जाता है कि गंभीर अपराधों में, विशेषकर उन अपराधों में जिनमें अपराधी शक्तिशाली, प्रभावशाली अथवा समृद्ध हैं, उनमें या तो जिनके प्रति अपराध किया गया है अथवा वे जो इसके साक्षी हैं, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से होते हैं।
- इसलिए इनकी सुरक्षा करना न्याय की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। यह योजना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

उद्देश्य

- किसी साक्षी को बिना डरे या बदले की कार्रवाई के भय के बिना न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष साक्ष्य देने के लिए समर्थ बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि आपराधिक मामलों की छानबीन, मुकदमे एवं सुनवाई के समय साक्षियों को धमकाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
- जो व्यक्ति अपराधिक मामलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए।
- साक्षियों में यह भरोसा उत्पन्न किया जाए कि वे निर्भीक हो कर सामने आएँ और कानून के लागू होने में पुलिस और न्यायालय को सहयोग करें।
- इस योजना का उद्देश्य साक्षियों और उनके परिवार के सदस्यों को डराये जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा उनके सम्मान और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से बचाने के लिए उपाय खोजना है।
- योजना के अनुसार साक्षी को नई पहचान देते हुए उसकी मूल पहचान को छिपाया जाए।
- योजना के अनुसार जिन साक्षियों को धमकी दी गयी है उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी जाए तथा यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें किसी सुरक्षित घर में ले जाकर रखा जाए।
- योजना में यह प्रावधान है कि साक्षी को डाक और फोन से मिल रही धमकी का अनुश्रवण किया जाए, जिससे धमकी देने वाले का पता लग सके।
- प्रत्येक राज्य में इस योजना पर आने वाले व्यय के लिए एक अलग साक्षी सुरक्षा कोष की व्यवस्था होगी।

गवाहों की तीन श्रेणियाँ

- श्रेणी "क" : इस श्रेणी में वे साक्षी आएँगे, जिनको अथवा जिनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है जिसके कारण वे जाँच-पड़ताल/मुकदमे के दौरान या उसके बाद भी अपना जीवन सामान्य ढंग से एक लम्बी अवधि तक नहीं चला पा रहे हैं।
- श्रेणी "ख" : इस श्रेणी में वे साक्षी अथवा उसके परिवार के लोग आते हैं, जिनकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा सम्पत्ति पर खतरा है। इस श्रेणी के अन्दर दी गई सुरक्षा मात्र जाँच-पड़ताल अथवा मुकदमे के दौरान ही दी जायेगी।

- श्रेणी "ग" : यह श्रेणी उन गवाहों के लिए है जिन्हें जाँच-पड़ताल के दौरान हल्का-सा खतरा है जैसे परेशान किया जाना अथवा गवाह या उसके परिवार के लोगों को धमकी दिया जाना अथवा प्रतिष्ठा अथवा सम्पत्ति पर खतरा।

इंडिया वाटर इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन

इकनोमिक टाइम्स, (05 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट त्रिदिवसीय शिखर सम्मेलन (5-7 दिसम्बर) को आरम्भ किया गया।
- इसका आयोजन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा (NMCG) तथा गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा दिया गया है।

क्या है?

- यह एक वार्षिक आयोजन है, जहाँ गंगा नदी घाटी के कायाकल्प से जुड़े हुए व्यक्ति जमा होते हैं।
- इसमें देश में चल रही जल से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मॉडल बनाने के विषय में चर्चा एवं संवाद होता है।
- इस वर्ष होने वाली चर्चा गंगा नदी घाटी के कायाकल्प पर केन्द्रित होगी।
- इस शिखर सम्मेलन में कई देश के लोग आएँगे तथा भारत और विदेश में हुए तकनीकी नवाचारों, अनुसंधानों, नीतिगत ढांचों और वित्त-पोषण मॉडलों के बारे में चर्चा की जायेगी।
- सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें से कुछ हैं – डाटा संकलन (सेंसर, LIDAR, मॉडल आदि), हाइड्रोलजी, ई-प्रवाह, कृषि, अपशिष्ट जल आदि।

गंगा वित्तपोषण मंच

- इस सम्मेलन में पहले गंगा वित्तपोषण मंच का अनावरण किया गया, जिसमें कई संस्थान प्रतिभागिता करेंगे और आपसी ज्ञान और सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।
- यह मंच ऐसे वित्तीय संस्थानों और निवेशकों को एक मंच पर लाएगा, जो 'नमामि गंगे' कार्यक्रमों में रूचि रखते हैं।

जलवायु जोखिम सूचकांक-2019

इंडियन एक्सप्रेस, इकनोमिक टाइम्स, (05 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में एक स्वतंत्र विकास संगठन जर्मनवॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक-2019 जारी किया गया है।
- इस सूचकांक में भारत को पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर 14वें स्थान पर रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस रैंकिंग में म्याँमार तीसरे, बांग्लादेश सातवें, पाकिस्तान आठवें और नेपाल ग्यारहवें स्थान पर है।
- यह सूचकांक स्पष्ट करता है कि भारत के चारों पड़ोसी देश चरम मौसमी घटनाओं द्वारा अधिक प्रभावित क्यों होते हैं।
- यह सूचकांक मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में मौसमी घटनाओं (तूफान, बाढ़, भयंकर गर्मी इत्यादि) के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण करता है।
- साथ ही यह सूचकांक इन प्रभावों का लेखा-जोखा पूर्णरूप में और साथ ही संबंधित शर्तों के साथ रखता है।

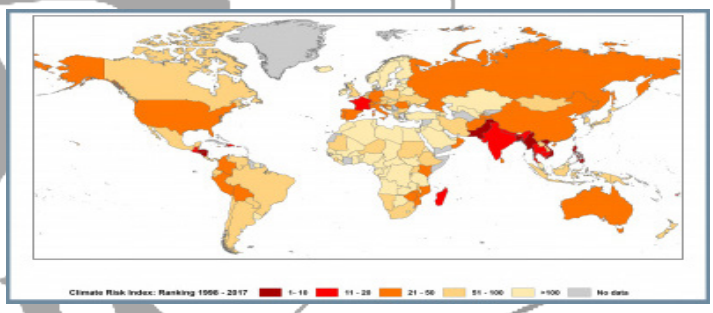

जलवायु जोखिम सूचकांक-2019

- वर्ष 1998-2017 के दौरान भारत में 73,212 लोग चरम मौसमी घटनाओं के शिकार बने।
- इसी समयावधि में चरम मौसमी घटनाओं के कारण भारत की वार्षिक औसत मौतों की संख्या 3,660 थी, जो कि म्याँमार की वार्षिक औसत मौतों की संख्या 7,048 के बाद दूसरी सर्वाधिक औसत संख्या है।
- जनसंख्या के समायोजन के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को सूची में भारत के ऊपर रखा गया है।
- रिपोर्ट में वर्ष 2017 में इन तीन देशों में हुई भारी बारिश का भी जिक्र किया गया है, जिसने 4 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और जिसके कारण लगभग 1,200 मौतें हुई।
- श्रीलंका, जिसकी 20 वर्षों की रैंकिंग 31वीं है, वर्ष 2017 (इस वर्ष भारी बारिश और भूस्खलन से 200 से अधिक मौतें हुई) में दूसरे रैंक पर है।
- इसके विपरीत म्याँमार और पाकिस्तान, जो कि 1998-2017 की सूची में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 15 देशों में शामिल हैं, वर्ष 2017 की सूची में क्रमशः 69वें और 33वें स्थान पर हैं।

वैश्विक आंकड़े

GERMANWATCH

- प्यूर्टो रिको (150 मौतें/वर्ष), होंडुरास (302 मौतें/वर्ष) और म्याँमार (7048 मौतें/वर्ष) को इस 20 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक 3 जलवायु जोखिम से प्रभावित देशों के रूप में पहचाना गया है।
- चीन (1240 मौतें/वर्ष) इस सूची में 37वें, जबकि भूटान (1.65 मौतें/वर्ष) 105वें स्थान पर है।
- वर्ष 2017 की सूची के लिये प्यूर्टो रिको, श्रीलंका और डोमिनिका वर्ष 2017 में चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देश थे। इसके बाद नेपाल, पेरू और वियतनाम का स्थान है।
- प्यूर्टो रिको और डोमिनिका सितंबर 2017 में तूफान मारिया द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।
- कुल मिलाकर 1998 से 2017 की समयावधि में 5,26,000 से अधिक लोगों की मृत्यु और 3.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हानि 11,500 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण हुई।

संयुक्त युद्धाभ्यास 'हैंड-इन-हैंड'

बिजनेस स्टैण्डर्ड, Pib, **(06 Dec.)**

संदर्भ

- हाल ही में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य आयोजित किये जाने वाले हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई।
- इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत भारत और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और संपर्क के हिस्से के तौर पर प्रतिवर्ष युद्धाभ्यास हैंड-इन-हैंड आयोजित किया जाता है।
- वर्ष 2018 के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास चीन के चंगतू में 10 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच निकटतापूर्ण संबंध बनाना और उसे बढ़ावा देना इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य है।
- दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास से उनकी क्षमता भी बढ़ती है।
- वर्ष 2018 के अंत तक भारत पी-5 देशों (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन) के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और आसियान देशों (सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड) के साथ भी अभ्यास कर चुका होगा।

क्या है?

- इस युद्धाभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने अथवा आतंकवादी माहौल से मुकाबला करने में सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे।
- भारतीय सेना के 11 सिखली से भारतीय पक्ष की सैन्य टुकड़ियों का चयन किया गया है। जबकि तिब्बती सैन्य जिले की एक यूनिट से सैन्य टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेंगी।
- युद्धाभ्यास हैंड-इन-हैंड 2018 से दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी अधिक मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी और यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीनी स्तर पर सौहार्द्र कायम करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

भारत-रूस संयुक्त युद्धाभ्यास

- भारत की वायुसेना रूस की सेना के साथ जोधपुर में 'एवियाइंद्र' युद्धाभ्यास करेगी। यह अभ्यास 10 से 22 दिसंबर तक होगा।
- इससे पहले ऐसा युद्धाभ्यास भारत और रूस ने सितंबर में रूस के लाइपटेक में किया था।

प्रसाद योजना

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, (06 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने गंगोत्री व यमुनोत्री (उत्तराखंड), अमरकंटक (मध्य प्रदेश), पारसनाथ (झारखण्ड) को प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) योजना में शामिल किया।
- इसके पश्चात् प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किये गये स्थानों की संख्या बढ़कर 41 पहुँच गयी है।
- यह 41 स्थान 25 विभिन्न राज्यों से शामिल किये गये हैं।

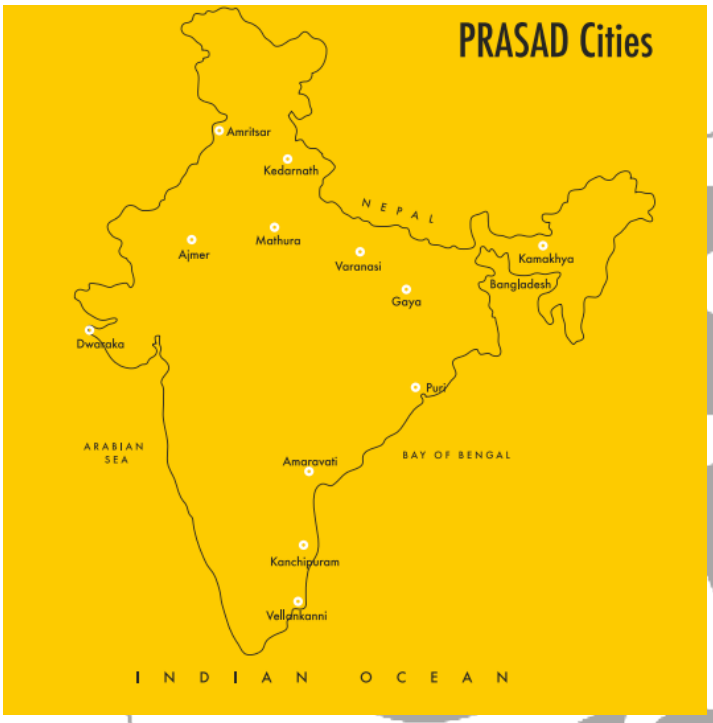

क्या है?

- इस योजना को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में लांच किया गया था।
- इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास सतत, योजनाबद्ध तथा प्रमुखता से करना है।
- इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य

- धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में वृद्धि करना।
- धार्मिक स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास।
- स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प तथा भोजन इत्यादि को बढ़ावा देना।
- इस योजना के तहत सड़क, रेल, जल मार्ग, एटीएम तथा मनी एक्सचेंज इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
- पर्यावरण मैत्री यातायात मार्ग, रोशनी के लिए नवीकरणीय उर्जा के स्त्रोत का उपयोग, पेयजल, पार्किंग, शौचालय, वेटिंग रूम, फर्स्ट ऐड केंद्र, कैफे, वर्षा आश्रालय, इन्टरनेट सुविधा इत्यादि।

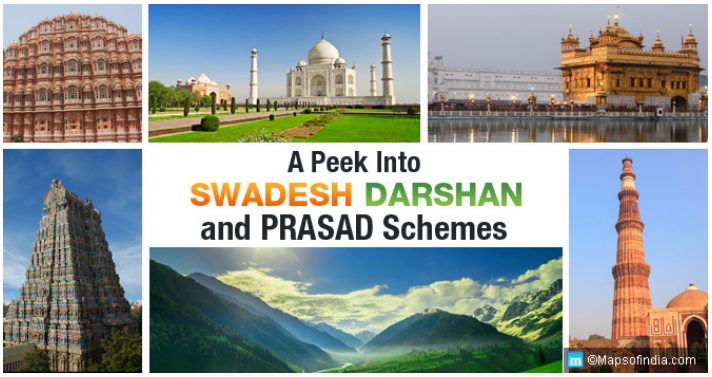

फंडिंग

- केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करता है।
- सार्वजनिक कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% फंडिंग प्रदान की जाती है।
- लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत भी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य किया जा सकता है।

रूस-भारत-चीन (RIC) शिखर सम्मेलन

लाइव मिंट, (06 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 12 वर्षों के बाद RIC (रूस-भारत-चीन) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका आयोजन G-20 शिखर सम्मेलन के बाद किया गया।
- इस सम्मेलन में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गयी।
- इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लिया।
- तीनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने, BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) तथा SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के द्वारा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की।
- इस दौरान आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गयी तथा इन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति प्रकट की गयी।

World Committed to Excellence

- जी-20 सम्मेलन 2018 का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया।
- यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाने वाला पहला जी-20 शिखर सम्मेलन था।
- यह जी-20 समूह की 13वीं बैठक थी। इसका आयोजन 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2018 के दौरान किया गया।
- इस वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मौरिसियो मक्री थे।
- इस सम्मेलन में चिली, जमैका, नीदरलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, रवांडा, सिंगापुर और स्पेन को भी आमंत्रित किया गया था।
- इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. 'साक्षी सुरक्षा' योजना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत लागू किया गया।
   2. 'साक्षी सुरक्षा' योजना के अंतर्गत चार श्रेणियाँ बनायी गयी हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. हाल ही में 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' तथा 'गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन' द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया वाटर इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया।
   2. इंडिया वाटर इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान गंगा वित्तपोषण मंच का गठन किया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

3. 'जलवायु जोखिम सूचकांक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. 2019 में भारत को इस सूचकांक में जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर 14वें स्थान पर रखा गया है।
   2. यह सूचकांक मृत्यु तथा आर्थिक क्षति से संबंधित मौसमी घटनाओं के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण करता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. 2018 में दिसंबर के अंत में भारत और चीन के मध्य 'हैंड इन हैंड' संयुक्त सैन्य अभ्यास शंघाई में किया जाएगा।
   2. 2018 में दिसंबर के अंत में भारत और सिंगापुर के मध्य 'एवियाइन्द्र' युद्धाभ्यास जोधपुर में किया जाएगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केवल अमरकंटक एवं पारसनाथ को शामिल किया गया।
   2. 'प्रसाद' योजना को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरु किया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. रुस-भारत-चीन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. हाल ही में इसका आयोजन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के पश्चात् किया गया।
   2. इस सम्मेलन के दौरान आतंकवाद एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गयी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

GS World Committed To Excellence